

UGC-CARE List-Social Sciences- No. 193

ISSN 0974-0074

राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

(National Refereed Journal of Social Sciences)



वर्ष 21 अंक 2
जुलाई-दिसम्बर, 2019

समाज विज्ञान विकास संस्थान
बरेली (उ.प्र.)

इस अंक में

1. सरदार बल्लभभाई पटेल और भारतीय विभाजन : एक ऐतिहासिक विश्लेषण 1-5
डॉ० गिरीश चन्द्र पाण्डेय
 2. महिला सशक्तीकरण और पंचायती राज 6-13
डॉ० जितेन्द्र कुमार पाण्डेय
 3. हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान में समाचार पत्रों की भूमिका 14-19
कुलदीप सिंह
 4. विवाह के लिए मानव तस्करी -एक वैयक्तिक अध्ययन 20-26
डॉ० रन्जू राठौर
 5. पिछड़ी एवं दलित जाति के किशोरों की व्यक्तित्व आवश्यकताओं का अध्ययन 27-30
डॉ. राजेन्द्र सिंह
 6. बच्चों व महिलाओं का अनैतिक व्यापार : मानवाधिकार पर प्रहार 31-37
डॉ. प्रीती द्विवेदी
 7. शिमला के बहु-सांस्कृतिक प्रवासियों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों का व्यवहार: 38-43
एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
वेद प्रकाश सिंह
 8. स्वतंत्रयोत्तर भारत में ग्रामीण दलित महिलाओं की प्रस्थिति: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 44-51
रामवृक्ष द्विवेदी
 9. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा एक अध्ययन 52-59
भरत उपाध्याय
डॉ आराधना सेठी
 10. हिन्दी सिनेमा में कश्मीर का चित्रण 60-68
राहुल कुमार
 11. गौतम बुद्ध पुस्तकालय, बी.बी.ए.यू., लखनऊ में डिजिटल सेवाओं और 69-75
सुविधाओं के साथ उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि: एक अध्ययन
रश्मि गंगवार
डॉ. शिल्पी वर्मा
 12. मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति: एक तुलनात्मक अध्ययन 76-83
गुलाव देवी
डॉ. शिल्पी वर्मा
-

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान में समाचार पत्रों की भूमिका

□ कुलदीप सिंह

पर्यावरण प्रदूषण ने समस्त विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। समय-समय पर विश्व की विभिन्न संस्थाएँ इसके खतरे के बारे में आगाह करती रहती हैं। इससे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। हर साल समाचार सुनने को मिलते हैं कि हिमखंड पिघल रहे हैं¹ और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है² लेकिन तमाम विचार मंथनों के बावजूद मनुष्य इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहा है और प्रकृति का सीमा से अधिक दोहन करता जा रहा है।

प्रकृति ने मनुष्य को धरती, वायु और जल के रूप में अनेक अमूल्य उपहार दिये हैं। लेकिन वह इनका प्रयोग करने के बजाए इनको लूटने में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश जिसे कि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का खूब दोहन हो रहा है। 1962 में सतलुज नदी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई और जल विद्युत बनाने के लिए भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया। डैम बनने से इस नदी के आस-पास की वनस्पति और जैव विविधता को काफी नुकसान हुआ था।³ साथ ही इस नदी के जल प्रवाह को रोक कर बिलासपुर जिले में बनी गोविंद सागर झील में कई गांव के साथ साथ जीव-जंतु और पेड़-पौधे हमेशा के लिए जलमग्न हो गए। कुछ यही हाल पौंग डैम बनने से व्यास नदी के आसपास के इलाकों का हुआ। विस्थापित⁴ लोग अभी भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे

हैं⁵ मनुष्य तो लड़ सकता है लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले हजारों प्रजातियों के जीवों का क्या हुआ होगा, किसी को पता नहीं है।

इन डैमों और बांधों को निर्माण उर्जा की जरूरतों और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया था। लेकिन एक समस्या का निदान तो हो गया और साथ ही साथ कई अन्य पैदा हो गईं। एक रिपोर्ट के अनुसार उर्जा का प्रयोग गर्मी, ठंड, भोजन बनाने, कृत्रिम रोशनी, उद्योगों, कृषि और यातायात के लिए किया जाता है। अगर इन सभी गतिविधियों के लिए हम उर्जा का सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में विकास और यहाँ तक की मनुष्य जीवन भी खतरे में पड़ सकता है।⁶

सतलुज नदी पर ही बने करछम-वांगतू जल विद्युत संयंत्र ने भी किन्नौर में सतलुज घाटी पर गहरा असर किया है। यहाँ पर 1000 मेगावॉट जलविद्युत बनाई जाती

है। इन्वाइरन्मेन्टल जस्टिस ऐटलस (Environment Justice Atlas) के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से यहाँ की जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता, वनों, जल प्रदूषण और भूमिगत जल संसाधनों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है जिसके कारण से यहाँ पर सूखे और मरुस्थल बनने का खतरा बढ़ गया है।⁷ बांधों के बनने के कारण से मृदा की आद्रता में भी काफी बदलाव आया है और उसका परिणाम पारिस्थितिकी को भुगतना पड़ रहा है। यही दशा हिमाचल में बहने वाली सभी नदियों की हो गई है। इनका पारिस्थितिकी तंत्र विकास की भेंट चढ़ गया है या फिर चढ़

प्रकृति ने मनुष्य को असंख्य उपहार दिये हैं लेकिन मनुष्य के लालच के कारण इनका अत्यधिक दोहन हुआ है। इसी के परिणामस्वरूप अब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने के कगार पर पहुँच गया है। प्रदूषण ने पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया है। जल, थल और वायु सभी क्षेत्रों में अब इसका खतरा मंडरा रहा है। प्रदूषण के प्रभाव से देवभूमि हिमाचल भी नहीं बच पाई है। प्रस्तुत शोध लेख के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि समाचार पत्र इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से प्रकाशित कर रहे हैं। शोध अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'द टूरन' ने हिन्दी समाचार पत्र 'दिव्य हिमालय' की तुलना में पर्यावरण से संबंधित समाचारों को अधिक महत्ता प्रदान की है। शोध से यह भी स्पष्ट हुआ कि पनविजली परियोजनाओं और सीमेन्ट की फैक्ट्रियों से होने वाली पर्यावरण की हानियों के समाचार भी प्रकाशित नहीं हुए।

□ असिस्टेंट प्रोफेसर, नव मीडिया विभाग, हिमालय प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हि.प्र.)

रहा है। प्रकृति के साथ हो रही इस भारी छेड़छाड़ के कारण से बादल फटने⁹ जैसी आपदाओं की संख्या भी बढ़ गई है जिससे कई बार भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ है।¹⁰

यहीं नहीं विशालकाय सीमेंट के प्लांट भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तो आगे की ओर ले जा रहे हैं लेकिन पर्यावरण पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।¹¹ इकानमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में अंबुजा सीमेंट पांच मिलियन टन प्रति वर्ष चूना पत्थर के खनन की क्षमता रखता था।¹² बिलासपुर जिले के बरमाना में बने एसीसी प्लांट और सोलन जिले के दाड़लाघाट में बने अंबुजा सीमेंट प्लांट के कारण से खनिजों का दोहन किसी से छिपा हुआ नहीं है। चूना पत्थर के खनन के कारण यहां पर कई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ समतल हो गई हैं और इसके कारण विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों का अस्तित्व खत्म हो गया है। साथ ही चूना पत्थर को जमीन के नीचे से निकालने के लिए बिस्फोट करने के कारण से भी यहां के पारिस्थितिकी तंत्र को खासा नुकसान हुआ है।¹³

यही नहीं इन फैक्ट्रियों के कारण धूल के साथ साथ बहुत छोटे धूल के कण पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं साथ ही कई प्रकार की बीमारियों के कारण भी बन रहे हैं।¹⁴ साल 2018 में संघर्ष समिति बरमाना के बैनर तले ग्रामीणों को न्यायालय और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। लोगों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए एसीसी से पूछा कि प्रदूषण संबंधित नियमों का उल्लंघन करने की एवज में उनके उत्पादन को क्यों नहीं रोका जाए।¹⁵ द ट्रिब्यून में छपी एक खबर, “नाइटमेयर ऑन एनएच 21” के मुताबिक सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतारें होने के कारण से आम लोगों और सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।¹⁶ साथ ही ट्रकों में सीमेंट, चूना, पत्थर और कोयला ढोने से ध्वनि प्रदूषण¹⁷ और वायु प्रदूषण कई गुणा बढ़ जाता है। खास कर ध्वनि प्रदूषण उन इलाकों में बहुत बढ़ गया है जो कि इन फैक्ट्रियों के निकट हैं।¹⁸ कथित तौर पर फैक्ट्री मालिक ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी भूल जाते हैं। लेकिन सरकार ने उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए बाध्य करते हुए कुल लाभ का दो प्रतिशत, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

के अंतर्गत खर्च करना अनिवार्य बनाया है। इसी कड़ी में एसीसी ने साल 2014,15 और 16 के लिए अपना कुल लाभ 936.71 करोड़ रुपए दर्शाया और इसमें से देश भर में अपनी औद्योगिक इकाइयों के इलाके में 18.73 करोड़ रुपए खर्च किए।¹⁹ वहीं अंबुजा सीमेंट कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2018 के अनुसार कुल लाभ में से 53.46 करोड़ रुपए सीएसआर के लिए पूरे देश में खर्च किया गया है, जोकि कुल लाभ का 4.20 प्रतिशत बनता है।²¹ सीएसआर के खर्च को लेकर अकसर फैक्टरी मालिकों पर इसके इस्तेमाल करने में कथित तौर पर गड़बड़ियां करने के आरोप लगते रहे हैं।²² अगर इस खर्च के मुकाबले हिमाचल में हुए पर्यावरण नुकसान पर नजर डाली जाए तो वह इससे कई गुना ज्यादा हुआ है।

देवभूमि में हो रहे प्रदूषण के एक दूसरे पहलू पर भी दृष्टि डालते हैं। अकसर इंसान पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए फैक्ट्रियों को ही जिम्मेदार मानता है लेकिन हिमाचल में तथाकथित शहरीकरण ने भी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अव्यवस्थित भवन निर्माण के कारण से भी यहां की प्राकृतिक सुंदरता तो धूमिल हुई है साथ ही में इस अंधाधुंध दौड़ के कारण से प्राकृतिक संसाधनों का भी अत्याधिक दोहन हुआ है। स्थिति अब यह बन गई है कि पहाड़ों की रानी, शिमला में अब देवदार के जंगलों की जगह कंकरीट के जंगलों ने ले ली है। शिमला जो कि लगभग 16,000 - 25000 लोगों के निवास के लिए बनाया गया था अब यहां पर 2011 की जनगणना के मुताबिक 169,578 लोग रह रहे हैं।²³ इसी कारण यहां पर हुए बेतरतीब मकानों के निर्माण ने कई झरनों, छोटी नदियों, बावडियों की बली ले ली है। कई बावडियाँ सूख गई हैं तो कई के पानी को पीने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार शिमला शहर का 90 प्रतिशत हिस्सा 60 डिग्री की ढलान पर बनाया गया है। प्रदेश का 32 प्रतिशत हिस्सा बहुत अधिक नुकसान की आशंका वाले क्षेत्र में आता है और यहां पर कुल जनसंख्या की 60 प्रतिशत आबादी निवास करती है।²⁴ इसी साल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बनाए गए लगभग 90 प्रतिशत मकान सुरक्षित निर्माण के पैमानों पर खरे नहीं उतरते हैं।²⁵ अब यह भवन किसी “डैथट्रैप” से कम नहीं हैं।²⁶ इसका

उदाहरण हमें सोलन जिले के कुमारहट्टी में इसी साल (2019) में मिला था जब एक बहुमंजली इमारत भरभरा कर गिर गई थी और उसमें 14 लोगों की जान गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि इंसान लालच में नियम कायदों की भी परवाह नहीं करता है। उसका उद्देश्य लाभ कमाने तक ही सीमित रह गया है, चाहे इसके लिए उसे पर्यावरण तो दूर अपनी जान की ही कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए।

यही नहीं नए शहरों के बनने के कारण यहां पर वाहनों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। इसके कारण वायु प्रदूषण²⁷ के साथ ध्वनि प्रदूषण²⁸ की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं ट्रेफिक जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सड़कों को चौड़ा करने के लिए भी कई हजार पेड़-पौधों पर कुल्हाड़ी का हमला हुआ है। परवाणू-शिमला फोर लेन प्रोजेक्ट के कारण 65.5 हेक्टेयर वन भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) को स्थानांतरित किया गया है। सड़क के इस विस्तार के लिए लगभग 33,000 पेड़-पौधों को काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण को अभूतपूर्व नुकसान होगा।²⁹

इंसान के कभी लालच की वजह से तो कभी गलती से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अपार प्राकृतिक धन संपदा के धनी हिमाचल को इसका परिणाम कई बार उठाना पड़ता है। साल 2019 में हिमाचल प्रदेश में 500 के करीब जंगल में आग लगने की घटनाएं हुईं और इसमें 2600 हेक्टेयर के करीब जंगल खाक हो गए। इसके कारण एक तरफ वन्य जीव-जंतुओं को जानमाल की हानि हुई तो दूसरी ओर प्राणवायु देने वाले जंगल भी नष्ट हो गए।³⁰

अखबारों में प्रकाशित पर्यावरण संबंधी खबरों का तुलनात्मक अध्ययन : शोध के तुलनात्मक अध्ययन के लिए द ट्रब्यून (अंग्रेजी) और दिव्य हिमाचल (हिन्दी) को चुना गया। द ट्रब्यून, चंडीगढ़ से प्रकाशित होता है और दिव्य हिमाचल स्थानीय अखबार है और कांगड़ा से प्रकाशित होता है। शोध के लिए साल 2019 के सितंबर माह में प्रकाशित इन समाचार पत्रों की प्रतियों को शामिल किया गया।

पहले पन्ने पर पर्यावरण संबंधी खबरें : दिव्य हिमाचल के साल 2019 के सितंबर माह के फ्रंट पेज पर पर्यावरण से संबंधित कुल छह खबरें मिलीं। इनमें रोहडू

में बादल फटने, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान की तर्ज पर लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना अनुमति निर्माण की मंजूरी देने के लिए अध्यादेश, नई पर्यटन नीति, साथ ही इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक, रोप-वे (रज्जू मार्ग) बनाए जाने की खबरों को जगह दी गई। लेकिन रोप-वे की खबर में कहीं भी पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बात नहीं कही गई। द ट्रब्यून के पहले पन्ने पर भी पर्यावरण से संबंधित छह खबरें मिलीं। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग ना करने, यूनिसीसीडी के दिल्ली डिक्लोरेशन, हिमाचल सरकार द्वारा प्लास्टिक के कचरे को 75 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने, बद्दी में जिंक, कॉपर, लेड, और क्रोमियम का मिट्टी में मिलना, अवैध खनन को हरियाणा के ई-रवाना सिस्टम और पंजाब में किसानों द्वारा धान के पुआल को जलाने की खबरों को तरजीह दी गई। इन खबरों में जलवायु प्रदूषण से होने वाले खतरों के बारे में पाठकों को संदेश दिया गया।

संपादकीय पन्ने पर जलवायु संबंधी लेख : दिव्य हिमाचल में पर्यावरण से संबंधित 6 संपादकीय लेख थे। इनमें मुख्यतः वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग, हिमाचल में जलमार्ग का विस्तार करने, रिसाइकिल न होने वाले प्लास्टिक को सरकार द्वारा खरीदने का निर्णय, जल विद्युत और सौर उर्जा, अमेजन के जगलों में आग “कैसे जलते हैं दुनिया के फेफड़े,” और पौंग बांध विस्थापित परिवारों की ब्यथा बताया गया। इन संपादकीय लेखों में पर्यावरण को बचाने और सतत विकास के दिशा में चलने पर जोर दिया गया। द ट्रब्यून में इस माह के दौरान पर्यावरण से संबंधित सिर्फ दो संपादकीय लेख प्रकाशित हुए। इसमें दिल्ली सरकार द्वारा गाड़ियों के सम और विषम फॉर्मूले पर चलाना और सियाचिन ग्लेशियर को पर्यटकों के लिए खोलने पर लेख थे।

बैक पेज में पर्यावरण संबंधी कवरेज : सितंबर माह के द ट्रब्यून के अखिरी पन्ने "Back Page" पर पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित केवल तीन खबरें मलीं, जबकि दिव्य हिमाचल में इस पन्ने पर पर्यावरण के मुद्दों को कोई जगह नहीं दी गई। दिव्य हिमाचल में आस्था नाम से छह पन्नों का सप्ताहिक अंक आता है लेकिन इसमें कहीं पर भी पर्यावरण और खास कर पेड़-पौधों और जल, वायु और भूमि की महत्ता से संबंधित कोई भी

लेख प्रकाशित हुआ नहीं मिला। सितंबर माह में प्रकाशित इसके तीन अंकों में सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से संबंधित लेख मिले।

स्थानीय पन्नों पर पर्यावरण संबंधित खबरें : द ट्रब्यून में प्रदेश की खबरों के लिए 'City Himachal Pradesh' के नाम से हर रोज तीन से चार पन्ने प्रकाशित होते हैं। इनमें हर रोज घटने वाली घटनाओं के समाचार दिए जाते हैं। सितंबर माह में "City Himachal Pradesh" में पर्यावरण से संबंधित 26 खबरों को प्रकाशित किया। इन खबरों में प्रदेश में हो रहे अवैध खनन, प्लास्टिक से पर्यावरण को नुसान पर सरकार को हाईकोर्ट की नसीहत, ध्वनि प्रदूषण, ऐतिहासिक रिज मैदान के लगातार धंसने, दूषित पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, प्रदेश के पर्यटक स्थलों में रोप-वे बनाने की खबरों को जगह दी गई। 17 सितंबर को द ट्रब्यून ने एच.पी. बागवानी उत्पादों का विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के परवाणू स्थित फैक्टरी द्वारा फैलाए जा रहे वायु प्रदूषण की खबर को सचित्र प्रकाशित किया। इन्हीं पन्नों पर "What Our Readers Say" के नाम से चार कॉलम की जगह दी गई है। इसमें पाठकों द्वारा भेजी गई पर्यावरण को संजोए रखने से संबंधित राय और परेशानियों को प्रकाशित किया जाता है।

दिव्य हिमाचल में "मेरा कांगड़ा" नाम से प्रकाशित स्थानीय ऐडिशन में पर्यावरण से संबंधित केवल 11 खबरें मिलीं, जबकि इसके हर रोज चार पन्ने प्रकाशित होते हैं। इनमें आदि हिमानी चामुंडा रोप-वे को मिली फोरेस्ट क्लीयरेंस की खबर को लीड खबर बनाया गया। लेकिन इसमें कहीं पर भी पेड़ों के कटने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बात इंगित नहीं की गई। इसके अलावा, खनन माफिया, प्लास्टिक का प्रयोग ना करने, पौंग झील में विदेशी परिंदों के आगमन की खबर को सचित्र जगह दी गई। भू-जल स्तर में सुधार, घर-घर से कूड़ा उठवाने, बारिश के पानी को सहेज कर रखने के खबरों को प्रकाशित किया गया।

विशेषांक में पर्यावरण संबंधित खबरें : शोधार्थी के द्वारा किए गए अखबारों के तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि द ट्रब्यून सप्ताह में एक बार पूरा पन्ना "इन फोकस इनवायरमेंट" पर्यावरण प्रदूषण और जैव विविधता पर मंडरा रहे खतरों के लिए समर्पित किया गया है। इनमें प्रकाशित लेखों में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस

के उत्सर्जन पर चिंता जताई गई साथ ही शहरीकरण के कारण पैदा हो रहे कूड़ा करकट से पर्यावरण को नुकसान होने पर भी विचार किया गया। "इन फोकस ग्राउंड वाटर" में भू-जल स्तर के गिरते स्तर पर विस्तार से लेख प्रकाशित किया गया। 30 सितंबर 2019 को प्रकाशित "बैटलिंग डेजर्टिफिकेशन" में मृदा संरक्षण पर जोर दिया गया और बढ़ते रेगिस्तानों पर चिंता जताई गई। इस लेख के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीती में भी लगातार मरुस्थलीकरण हो रहा है। जबकि दिव्य हिमाचल में पर्यावरण पर मंडराते खतरों पर कोई पन्ना प्रकाशित नहीं होता है। इसमें "अपनी माटी" शीर्षक से प्रकाशित होने वाले पन्ने पर किसानों और बागवानों को जानकारी देने के लिए समर्पित किया है साथ ही "हिमाचल कम्पीटीशन रिव्यू" का साप्ताहिक अंक आता है। इसमें "हिमाचल का भौगोलिक परिचय" नाम से तीन या चार कॉलम का लेख आता है जिसमें भूगोल और पर्यावरण पर प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में चर्चा की जाती है।

निष्कर्ष : ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्यूलेशन की जनवरी-जून 2019 के आंकड़ों के अनुसार हिन्दी अखबारों की विक्री अंग्रेजी अखबारों की तुलना में दुगुनी है³¹ Indian Readership Survery (Q 1 2019)³² साल 2017 में हिंदी अखबारों के पाठकों की संख्या 16.8 प्रतिशत थी जो कि साल 2019 की पहली तिमाही में बढ़कर 17.2 प्रतिशत हो गई। वहीं वर्ष 2017 में अंग्रेजी अखबारों की पाठकों की संख्या 2.7 प्रतिशत थी जो की वर्ष 2019 की पहली तिमाही में सिर्फ 0.2 प्रतिशत बढ़ कर 2.9 रही। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के Regularity Report of Newspapers (जनवरी-सितंबर 2019)³³ आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ से प्रकाशित होनी वाली द ट्रब्यून की 1,61,156 प्रतियां और दिव्य हिमाचल (धर्मशाल और शिमला) की 95654 प्रतियां विकीं।

शोध में पाया गया कि दोनों अखबारों में द ट्रब्यून में पर्यावरण से संबंधित खबरों को दिव्य हिमाचल की तुलना में काफी अधिक स्थान दिया गया। दिव्य हिमाचल के फ्रंट पेज, संपादकीय पन्ने, बैक पेज, मेरा कांगड़ा, सप्ताहिक विशेषांक को मिला कर सितंबर महीने में इनके 226 पन्ने प्रकाशित हुए। वहीं पर्यावरण के विषय पर सिर्फ 26 खबरें प्रकाशित हुईं। द ट्रब्यून के फ्रंट पेज, संपादकीय पन्ने, बैक पेज, सिटी हिमाचल और सप्ताहिक विशेषांक को मिलाकर सितंबर महीने में 216 पन्ने प्रकाशित हुए। इनमें ट्रब्यून

ने 48 खबरों को प्रकाशित किया। साथ ही ट्रब्यून ने जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के बढ़ते खतरे से संबंधित जानकारियों और सूचनाओं के लिए विशेषांक भी निकाले लेकिन दिव्य हिमाचल में इस प्रकार की कोई पहल नहीं देखी गई। हिन्दी अखबारों की मांग ज्यादा होने के नाते दिव्य हिमाचल को अपनी संपादकीय नीति में बदलाव लाने की जरूरत है और पर्यावरण संबंधी जानकारियों की संख्या को बढ़ाना चाहिए।

शोध के लिए ली गई दोनों अखबारों में दूरगामी इलाकों में पनबिजली बनाने वाली इकाइयों के कारण हो रहे

पर्यावरण को नुकसान और सीमेंट की फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण से संबंधित एक भी खबर नहीं मिली। समाचार पत्रों को पर्यावरण से संबंधित खबरों को प्रकाशित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इन्हें प्रदेश के दूरगामी इलाकों में जहां विभिन्न पनबिजली परियोजनाएं और फैक्ट्रियाँ लगी हैं वहां पर अपने पत्रकारों को तैनात करना होगा तभी इन इलाकों से खबरें पाठकों तक पहुंच पाएंगी और पर्यावरण को संजोए रखने में अहम भूमिका निभा पाएंगे।

Reference

1. Azama M. F, Wagnon P, Vincent C, Ramanathan A.L, Kumar N, Srivastava S, Pottakkal J.G, Chevalliere P, (2019). Snow and ice melt contributions in a highly glacierized catchment of Chhota Shigri Glacier (India) over the last five decades, Journal of Hydrology, Volume 574, July 2019, Pages 760-773
2. Kaushik Saurabh, Jaydeo K. Dharpure, P.K. Joshi, AL Ramanathan & Tejpal Singh (2019) Climate change drives glacier retreat in Bhaga basin located in Himachal Pradesh, India, Geocarto International, DOI: 10.1080/10106049.2018.1557260
3. Kaur H. (2019) Satluj Floodplain: A Hazardscape. In: 'Moving towards Risk' - A Melancholic Story of Punjab Satluj Floodplain. Springer Earth System Sciences. Springer, Cham
4. Mishra A (2019). Issues of Large-scale Dam Resettlement and Rehabilitation: Case of Bilaspur, Himachal Pradesh, Indian Journal of Public Administration
5. <https://www.indiatvnews.com/news/india/bhakra-beas-project-himachal-pradesh-chief-minister-jai-ram-thakur-551133>
6. Idl-bnc-irdc.dspacedirect.org, Special Session World Commission on environment and development 1987
7. <https://ejatlas.org/conflict/karchham-wangtoo-project-hp-india>
8. <http://ijprvd.info/v69n12.html> (Dharamveer, Dasgupta Sabyasachi, 2019, Volume 69 No. 1&2, Impact of river flow diversion on soil moisture and growth of Pinus wallichiana dominated riparian vegetation)
9. Thakur Shivani, Chandel Vishwa B.S (2016). Geographical Perspective on hydro-meteorological disasters in Himachal Pradesh, India, International Journal of Environmental Science, Vol. 6, Issue 6, P 1090-95
10. <https://hindi.news18.com/news/himachal-pradesh/reckong-peo-heavy-rainfall-in-himachal-cloud-burst-in-kinnaur-bridge-washed-away-kaza-highway-closed-hpvk-2306677.html>, Arun Negi, Recong Peo
11. Lamare R.E, Singh O.P (2019), Effect of cement dust on soil physic-chemical properties around cement plants in Jaintia Hills, Meghalaya, Environmental Engineering Research
12. <https://m.economictimes.com/industry/indly-goods/svs/cement/ambuja-cements-gets-notice-halts-mining-hp/articleshow/30299013.cms> (PTI)
13. http://www.samataindia.org.in/mici/attachments/article/44/Environmental%20issues_cement%20Plants.pdf
14. Kourtidis K, Rapsomanikis S, Zerefos C, Georgoulas A.K, Pavlidou E (2014). Severe particulate pollution from the desposition practices of the primary materials of a cement plant, Environmental Science and Pollution Research, Volume 21, Issue-16, pp 7996-9808
15. <https://www.tribuneindia.com/news/weekly-pullouts/himachal-tribune/cement-industry-raises-heat-and-dust/698348.html>, Pratibha Chauhan
16. Sh. Goswami (2009). "Road Traffic Noise: A Case Study of Balasore Town, Orissa, India". International Journal of Environmental Research, 3, 2, 2009, 309-318. doi: 10.22059/ijer.2009.58
17. Deb Dulal. (2011) Tripura. Traffic Noise Prediction Model in Agartala City, India. International Review of Applied Engineering Research.. 1. 93-98.

-
18. <https://www.tribuneindia.com/2007/20070815/himplus1.htm>, Kuldeep Chauhan
 19. Hunashala R. B., Patil Y.B. (2012) Assessment of Noise Pollution Indices in the City of Kolhapur, India, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 37, 2012, Pages 448-457
 20. <https://www.acclimited.com/source/new/csr/ACC-CSR%20Annual-Report-2017.pdf>
 21. <https://www.ambujacement.com/Upload/PDF/AmbujaCementAnnualReport2018Web.pdf>
 22. Arora, B. & Puranik, R. (2004). A Review of Corporate Social Responsibility in India. *Development*, 47(3), 93-100.
 23. Kumar, A., & Pushplata (2015). City Profile: Shimla. *Cities*, 49, 149-158.
 24. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/buildings-in-himachal-are-a-death-trap-courtesy-haphazard-construction-violation-of-safety-laws/articleshow/70235812.cms>
 25. <https://www.financialexpress.com/india-news/himachal-pradesh-buildings-vulnerable-to-collapse-do-not-follow-safety-norms/614290/>, IANS
 26. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/buildings-in-himachal-are-a-death-trap-courtesy-haphazard-construction-violation-of-safety-laws/articleshow/70235812.cms>
 27. Kumar P., Siddiqui A., Gupta K., Jain S., Bharath B.D., Maithani S. (2019) Understanding Urban Environment in Northwest Himalaya: Role of Geospatial Technology. In: Navalgund R., Kumar A., Nandy S. (eds) *Remote Sensing of Northwest Himalayan Ecosystems*. Springer, Singapore
 28. https://www.scirp.org/html/2-1610193_93155.htm
 29. <https://hillpost.in/2016/05/33k-trees-to-be-cut-for-parwanoo-shimla-highway/106290>
 30. https://www.business-standard.com/article/news-ani/over-500-cases-of-forest-fires-in-himachal-pradesh-119061101441_1.html
 31. <http://www.auditbureau.org/index.html>, retrieved on 23-Oct-2019, 5.18 p.m.
 32. <https://mruc.net/uploads/posts/8e428e54a95edcd6e8be593a7021a185.pdf> retrieved on 23-Oct-2019, 6.19 p.m.
 33. [http://www.davp.nic.in/Upload/\(S\(335eelac0u5lws45vf3vrg55\)\)/Regularity_report.aspx](http://www.davp.nic.in/Upload/(S(335eelac0u5lws45vf3vrg55))/Regularity_report.aspx) retrieved on 23-Oct-2019, 6.01 p.m.